SHRI S. M. BANERJEE : Conversion of the Press Trust of India and other news agencies into a Corporation was delayed because they were trying to bring a legislation for supposed to be diffusion of ownership and control of newspapers. I would like to know as to why there is the delay, why conversion of the PTI into a public corporation is being delayed though there was a clear recommendation by the Press Council.

SHRI I. K. GUJRAL : The Press Council made no such recommendation to us.

SHRI S.M. BANERJEE : It was the recommendation of the Press Commission that the PTI should be taken over and converted into a corporation. This House was told by Shrimati Nandini Satpathy when she was the I & B Minister that this was delayed because of this Bill. I want to know why the Bill is being delayed now.

SHRI I. K. GUJRAL : The Press Commission did suggest and some steps were taken in the past in the light of the Press Commission's report also. We have also felt that some further action is needed and as part of this Bill we will deal with News Agencies also.

आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी करना

*328. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए लाइसेंस देने के बारे में हाल ही में कोई नया निर्णय लिया गया है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) देश में उन पिछड़े हुए जिलों के नाम क्या हैं जहां आदिवासी रहते हैं तथा जहां सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ग) क्या राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क). पिछड़े क्षेत्रों से मिलने वाले आवेदन पत्रों को तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता और औद्योगिक लाइसेंस नीति की परिसीमा में प्राथमिकता देने की सरकार की स्वीकृत नीति है।

(ख) से (घ). आदिवासी आबादी वाले पिछड़े जिलों में स्थापित किये गये उद्योगों के संबंध में उपलब्ध जानकारी निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	उद्योग का नाम
उदयपुर	(1) सीमेंट का कारखाना
	(2) जिंक स्मेल्टर
चित्तौर गढ़	सीमेंट का कारखाना, अन्य सीमेंट एकक की स्थापना होने वाली है।
सिरोही	*एक सीमेंट कारखाना खोला जाने वाला है।
डूंगरपुर	शीशे की बोतलें बनाने और डब्बों के (कन्टेनर) संयंत्र की स्थापना के लिये आशयपत्र जारी किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रश्न यह था कि जिन आदिवासी इलाकों में आर्थिक और तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं हैं क्या वहां पर कोई औद्योगिक विकास नहीं होगा क्योंकि आदिवासी इलाकों में प्रकृति की देन के रूप में जो साधन उपलब्ध हैं उन की सहायता से भी वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं खोली जाती हैं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि जब तक आदिवासी इलाकों में तकनीकी और आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक उन का विकास नहीं होगा। मैं जानना चाहता

*सरकारी क्षेत्र।

है कि तकनीकी और आर्थिक साधन उपलब्ध करना सरकार का काम है या आदिवासी लोगों का?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: प्रश्न के उत्तर में मैं ने यह बतलाया है कि सरकार की यह नीति है कि पिछड़े इलाकों में उद्योग धन्धे स्थापित करने के काम को प्राथमिकता दे। मैं ने यह नहीं कहा है कि वहां उद्योग धन्धे नहीं लगाये जायेंगे। मैं ने तो कहा कि सरकार उन इलाकों को प्राथमिकता देती है।

जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां पर चार आदिवासी जिले हैं: उदयपुर, चित्तौरगढ़, सिरोही और डूंगरपुर। इन चारों जिलों में उद्योगधन्धे स्थापित किये गये हैं। उदयपुर में सीमेंट का कारखाना, और जिंक स्मेल्टर, चित्तौरगढ़ में सिमेंट का कारखाना, अन्य सीमेंट एकक की स्थापना होने वाली है, सिरोही में एक सीमेंट का कारखाना खोला जाने वाला है और डूंगरपुर में शीशे की बोतलें बनाने और डब्बों के (कन्टेनर) संयंत्र की स्थापना का विचार है।

श्री मूलचन्द डागा: मंत्री महोदय ने तो कहा है कि जहां पर तकनीकी और आर्थिक साधनों की सम्भावनायें हैं वहां औद्योगिक लाइसेंस नीति की परिसीमा में प्राथमिकता देने की सरकार की स्वीकृत नीति है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह जानते हैं कि सवाई माधोपुर में जो तेलशोधक कारखाना खुलने वाला था, जहां पर आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं, उस को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाया गया। राजस्थान में जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं.....

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा प्रश्न कीजिये, आर्गूमैंट मत कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा: मंत्री महोदय का उत्तर यह था कि जहां आर्थिक और तकनीकी साधन उपलब्ध होंगे वहीं औद्योगिक कारखाने खोले जायेंगे, लेकिन अब कहते हैं कि...

अध्यक्ष महोदय: जब आप प्रश्न पूछते हैं तो कुछ तो इस प्रकार कहिये कि क्या वजह है या क्या मंत्री महोदय बतला सकते हैं। प्रश्न की तरह पर तो उस को रखिये।

श्री मूलचन्द डागा: मेरा प्रश्न यह था कि जब तक आदिवासी इलाकों में आर्थिक और तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक वहां पर सरकार इंडस्ट्रीज को लगायेगी या नहीं।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: मैं ने बतलाया कि इन आदिवासी इलाकों में जहां पर साधन उपलब्ध हैं वहां राजस्थान के इन जिलों में सरकार ने ऐसे कारखाने खोलने के लिये अब तक क्या काम किया है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जिन इलाकों में साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां क्या किया जायेगा। तो जहां पर साधन उपलब्ध नहीं हैं वहां साधन उपलब्ध कराने के वास्ते कदम उठाये जायेंगे।

श्री लालजी भाई: मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि आदिवासी इलाकों को प्राथमिकता दी जायेगी। तो वह कब तक दी जायेगी?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: प्राथमिकता दी जा रही है। उदाहरणस्वरूप मैं ने चार जिलों के नाम बतलाये जहां कारखाने स्थापित किये गये हैं या किये जा रहे हैं।

SHRI PARIPOORNANAND PAINULI : The Ministr has rightly said and the working group of the Planning Commission long ago had recommended that in the backward areas they should set up new industries. How is it that during the yeat 1969-70 and 1970-71, only 91 industries are set up in the backward and the tribal areas out of a total of 752 industries set up during this period?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD: Location of industries in the backward areas is going up in 1969, 17 licences were given for setting up of industries in backward areas ; in 1970 this figure went up

to 59 and in 1971 it went up still further to 76.

श्री मान सिंह भौरा : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां ग्राप यह समझते हैं कि पंजाब आज इण्डस्ट्रियली फारवर्ड है, वहां वह बैकवर्ड स्टेट भी है। वहां जो लाइसेंस इंडस्ट्रीज लगाने के लिये दिये गये थे उन में से स्कूटर की इंडस्ट्री को वहां से यू पी में शिफ्ट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह फारवर्ड हो गया है बैकवर्ड में ?

SHRI R.S. PANDEY : This is a reflection on you. You are the Speaker; you come from Punjab; Punjab is not a backward area.

MR. SPEAKER : Persons establishing industries are still backward; it is suffering because of that. I am sorry I am also participating in the discussion....

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : Punjab is one of the most advanced and progressive States in the world, I should say. The per capita income of Punjab is the highest in the whole of India.

MR. SPEAKER : It is not because of your industry ; it is due to our own industry ; we are hard-working people.

SHRI R.S. PANDEY : Punjabis are most industrious, Sir.

DR. MAHIPATRAY MEHTA : Huge capital is lying idle which came from the refugees from Africa in the backward district of Kutch in Gujarat. What is it that Government wants to do to utilise this capital for the industrial development of that area ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : It is a separate question.

SHRI D.N. TIWARY : The hon. Minister has given the figures of industries established in backward areas. North Bihar is the most backward area. May I know how many industries were set up there during the last 10 years ? Except Barauni refinery there is no industry in the seven districts of North Bihar. May I know whether any steps are being taken to set up industries there and if so, what are the steps ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : I do not have the details. After the coming into being of the backward area scheme, certain new industries in the backward districts of North Bihar have been licensed.

SHRI D.N. TIWARY : I don't see any activity there in opening up of any new industry.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR SPEAKER : Every gentleman who is standing is under the impression that he is alone standing. He does not know that so many others are standing also. How is it possible to accommodate so many people ? I will pick up one from backward area, Shri Mohanty.

SHRI SURENDRA MOHANTY : Has there been any shift in the policy of industrialisation of the backward areas in view of Mr. Subramaniam's package plan for backward areas ? If so, what are the broad features of that change in policy.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : We are laying more and more emphasis on the development of the backward districts and also areas which are backward. Such areas are spotted out and project reports are prepared..............................

SHRI SURENDRA MOHANTY : My question is being evaded. I asked a specific question. Is there going to be a shift in the policy of industrialisation of the backward districts and backward areas

in view of Mr. Subramaniam's admitted 'package plan' which is in contradiction of the earlier scheme of development of backward areas ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE & TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): There is no change in the industrialisation programme. But my idea is this, namely that pushing in a few industries alone would not bring up the backward areas and make them forward with reference to the large masses of the people. Therefore, if we take into account the lagre masses of the people, the package programmes will have to be taken up, and that is being worked out.

SHRI SURENDRA MOHANTY : Is that his subjective assessment, or is it guided by any objective considerations?

श्री बी० पी० मौर्य : पिछले पच्चीस बरस में अनुसूचित जन जातियों का विकास और पिछड़े क्षेत्रों का विकास न के बराबर हुआ है। उनका विकास हो इसको ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार पिछड़े इलाकों के क्षेत्रफल और अनुसूचित जन जातियों की संख्या इन दोनों पर विचार करेगी और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए राशि अलग से सुरक्षित रखेगी?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अभी सरकार की नीति इन इलाकों के लिए राशि सुरक्षित रखने की नहीं है। लेकिन सरकार ने इन इलाकों में कारखाने स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश में कारखाना स्थापित किया है सिलाई का, उड़ीसा में स्थापित किया है राउरकेला का और छोटा नागपुर, बिहार में——

SHRI B.P. MAURYA : My question has not been answered. Will it be the policy of Government to allocate the funds on the basis of the backward areas and the population of the Scheduled Tribes? Let him say 'Yes' or 'No'.

SHRI C. SUBRAMANIAM : As far as financial allocation by Government is concerned, that would be only with reference to public sector projects. But public sector projects are only in the heavy industries area and their number is limited. Therefore, generally, it has got to be a case of pushing the private sector to these backward areas as much as possible, and allocation of specific funds does not arise. But I do agree that in spite of all our efforts to have more industrialisation in backward areas, for want of the infra-structure and other facilities there, even with all the inducements, industrialisation is not taking place as much as would like it to. But we shall make all efforts to provide this infrastructure at least in certain key areas in the backward districts and see that some industries come up there.

श्री फूलचन्द वर्मा : मूल प्रश्न आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का है। मध्य प्रदेश, देश का एक ऐसा प्रांत है जहां पर सब से अधिक आदिवासी रहते हैं। बसतर, सरगुजा, खारगोन, झाबुआ आदि ऐसे इलाके हैं जहां पर एक भी नया कारखाना स्थापित नहीं किया गया है, यह आप की स्टेटमेंट से पता चलता है। मध्य प्रदेश में तेल संयंत्र का कारखाना खुलने वाला था। टेलीफोन स्विच गीयर का भी खुलने वाला था। लेकिन एक राय बरेली चला गया और दूसरा इलाहाबाद चला गया। ये दोनों कारखाने मध्य प्रदेश में खुलने वाले थे। वह आदिवासी प्रान्त है। वहां हर तीन व्यक्तियों के पीछे एक आदिवासी या हरिजन है। उस प्रान्त में देश के सभी प्रान्तों के मुकाबले में आदिवासियों और हरिजनों की संख्या सब से अधिक है। वहां कोई नया कारखाना क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और जो ट्रांसफर किए गये हैं। वे क्यों किये गये हैं?

SHRI C. SUBRAMANIAM : The hon. Member is pleading on behalf of the Adibasis. These industries certainly are not

going to provide any employment opportunities for the Adibasis, because these require highly trained men, particularly the refineries and other sophisticated industries. In the name of Adibasis, certainly they can claim industries, but certainly it would not be for the benefit of the Adibasis themselves. Therefore, it has got to be a programme of giving proper training to the Adibasis and also taking up industries which would benefit them and which would give employment potential to them more than a question of pushing these sophisticated industries there.

SHRI VIRBHADRA SINGH : How many licences have been issued for setting up industries in the private or public sector in Himachal Pradesh and in the UP Hills, which the hon. Minister knows are very backward areas industrially, and will Government give special attention to industrialise these areas ?

MR. SPEAKER : That is a very specific question. If the hon. Minister is prepared to answer, I have no objection.

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : I would require notice for it.

DR H.P. SHARMA : The reply states very clearly that it is the accepted policy of Government to give preferential treatment to backward areas, subject only to one condition, namely that the techno-economic conditions would be feasible. There is a very specific case of shifting of the oil refinery from Sawoi Madhopur to Agra. Sawoi Madhopur is a backward district and the population there is Scheduled Tribe. There are no problems of techno-economic feasibility. Even then, why was the decision taken to shift it from Sawoi Madhopur to Agra. Would Government reconsider the decision ?

SHRI C. SUBRAMANIAM : This question should be put to the Petroleum and Chemicals Ministry.

SHRI KRISHNA HALDER : Bankura and Purulia are tow backward districts in West Bengal inhabited by Scheduled Tribes. May I know whether Government is going to open new factories in these two districts ?

SHRI SIDDHESHWAR PRASAD : The main question relates to Rajasthan.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह भाग देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है ।

SHRI C. SUBRAMANIAM : Hon. Members do not expect us to have figures in respect of all the districts in the whole of India. If the hon. Member is interested in these two districts, either he can write to me and I shall give him the information, or he can put a separate question.

Joint Sector for rapid Industrialization

*332. SHRI S.R. DAMANI : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether any policy has been evolved to implement the concept of joint-sector for rapid industrialization ;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, when a clear cut decision will be taken to remove the uncertainties in the investment climate ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) to (c) . A statement is laid on the Table of the House.

Statement

To secure the rapid growth of industries in a manner consistent with national needs and public interest, the Industrial Licensing Policy of the Government announced in February, 1970 envisages the concept of the Joint Sector through